R.N.I. No. RAJHIN/2020/79075

कागज़ की कश्ती

पाक्षिक समाचार पत्र

मो. 9829250181
ई-मेल : shiv.ksg@gmail.com
सम्पादक : शिवकुमार शर्मा

वर्ष - 6 | अंक - 19 | किशनगढ़, मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 | कुल पृष्ठ - 4 | (पाक्षिक) | मूल्य रु. 360/- (वार्षिक)

एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द रहेगी-हाई कोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा को रद्द करने वाले एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि पेपरलीक में लिप्त हुए लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि आरपीएससी में राजनीति के आधार पर चयन नहीं होना चाहिए और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कानून लाया जाना चाहिए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों पर फैसला सुनाते हुए दिए। खंडपीठ ने गत 19 जनवरी को सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

खंडपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और तत्कालीन सदस्य मंजू शर्मा और संगीता शर्मा सहित अन्य की अपीलों को भी खारिज किया। अदालत ने एकलपीठ की ओर से आरपीएससी की कार्यशैली को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दर्ज याचिका को भी रद्द किया है। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों ने अपील में एकलपीठ की ओर से दिए फैसले में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की गुहार की थी। असफल अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने परीक्षा रद्द करने की गुहार करते हुए कहा था कि आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से 35 दिन पहले तत्कालीन सदस्य रामूराम राइका को पेपर दिया था। कटारा ने अपने ड्राइवर के बेटे अजय प्रताप सिंह, रिश्तेदार विजय डामोर व राहुल कटारा, शिक्षक कुंदन, सहायक लेखाधिकारी संदीप कुमार व पुरुषोत्तम दाधीच, शिवसिंह एवं तत्कालीन पीएसओ राजकुमार यादव को भी पेपर दिया।

राइका ने बेटे-बेटी को यह पेपर दिया था। भर्ती में दोषियों की छंटनी मुश्किल है। इसलिए इसे रद्द किया जाए। इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, सफल अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था और दोषियों की छंटनी संभव है। वहीं कुछ चयनित अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि वे पुरानी नौकरी छोड़कर आए थे और जांच में वे बेदाग निकले हैं। ऐसे में भर्ती रद्द करना ठीक नहीं है।

आप ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को उनकी जगह दे दी। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखे पत्र में कहा कि सदन में पार्टी की तरफ से बोलने का समय न दिया जाए। राघव 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। पार्टी ने इस फैसले की वजह नहीं बताई है। अशोक मित्तल भी पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद हैं। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर हैं। 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे। राजनीति में आने से पहले वह कामयाब बिजनेसमैन रहे हैं। राघव चड्ढा ने लंबे समय से पार्टी से दूरी बना ली थी और आप को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। 27 फरवरी को जब सीबीई की अदालत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत मिली, तब भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था।

प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वैध पहचान पत्र दिखाकर मिलेगा 5 किलो का सिलेंडर

नई दिल्ली। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को राहत देते हुए उनकी रसोई गैस की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कहा है कि वे वैध पहचान पत्र दिखाकर एलपीजी वितरकर से सिलेंडर ले सकते हैं इसके लिए उनके पास पते का प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और लोग पेट्रोल और डीजल की घबराहट में खरीदारी तथा एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग से बचें। पीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और पिछले महीने से अब तक 3.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों में गैस आपूर्ति शुरू की गई है। सोमवार से उर्वरक संयंत्रों को गैस आपूर्ति छह माह की औसत खपत के लगभग 90 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। एलपीजी जमाखोरी और काला बाजारी पर कार्रवाई जारी है और 3700 से अधिक छापे मारे गए। सरकार का कहना है कि चालू यूरिया संयंत्रों को गैस आपूर्ति अब पिछले 6 महीनों की औसत खपत के लगभग 70-75 प्रतिशत पर स्थिर है। उपलब्ध भंडार और निर्धारित एलएनजी कार्गो आगमन को देखते हुए उर्वरक संयंत्रों को गैस आपूर्ति को बढ़ाकर लगभग 90 प्रतिशत की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों, जिसमें सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति शामिल है में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

एक फैमिली कोर्ट दूसरे फैमिली कोर्ट को नहीं कर सकता केस ट्रांसफर : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि एक पारिवारिक न्यायालय दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। केवल हाईकोर्ट या जिला न्यायालय को ही पारिवारिक न्यायालय के केस ट्रांसफर करने का अधिकार है। न्यायाधीश सुदेश बंसल व न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ओर से प्रशासनिक रूप में भेजे गए रेफरेंस पर आदेश दिया। कोर्ट ने कानूनी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि भरतपुर में एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर करने का निर्णय सही नहीं था, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी सभी पारिवारिक न्यायालयों को भेजने का आदेश दिया है।

समाचार पत्र की खबरों का स्रोत

समाचार पत्र के संवाददाता, PRO Ajmer, DIPR Jaipur, PIB Jaipur, दूरदर्शन भारत के माध्यम से तथा अन्य स्रोतों से समाचार पत्र की खबरों का प्रकाशन किया जाता है।

सम्पादक

SHRI RATANLAL KANWARLAL PATNI
GIRLS' COLLEGE, KISHANGARH
(PG College Affiliated to M.D.S. University, Ajmer)

B.A. | B.Com. (Pass Course & Hons.)
B.Sc. (Bio., Mathematics & Home Science)
BBA | BCA (AICTE Approved)
B.Sc.B.Ed. | B.A.B.Ed.*
(4-Year Integrated Programmes)
*Admission through PTET only
M.A. (Geography, Home Science & Hindi)
M.Sc. (Mathematics & Zoology)
M.Sc. (Computer Science)

All Govt. Scholarships Available
Attractive Rebate Policy up to 75% for Meritorious Students

NSS | NCC | Scouts & Guides (Rangers) | UBA | RKCL Courses
Sports Academy | Competitive Exam Preparation Classes
Counselling Sessions Available | Hostel Facilities Available Nearby

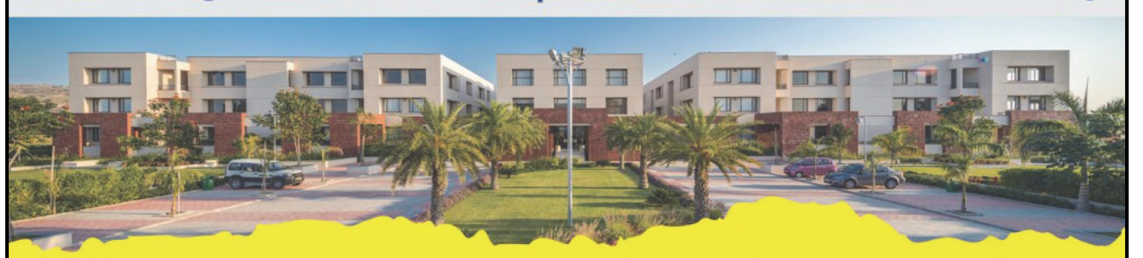

Ajmer Road, Madanganj-Kishangarh, 305801, District - Ajmer (Rajasthan)
Tel.: +91 1463 257000, WhatsApp @ +91 70730-77222
E-mail: info@rkgirlscollege.edu.in, Web: www.rkgirlscollege.edu.in

न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, प. बंगाल के अधिकारियों को लगाई फटकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले और बंधक बनाने की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गुरुवार को इसे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करने का एक 'दुस्साहसिक प्रयास' और न्यायालय के अधिकार को चुनौती करार दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गांव में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और उन पर हुए हमले के बाद इस मामले पर तत्काल सुनवाई की, हालांकि यह मामला गुरुवार की कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं था। न्यायालय ने राज्य में हुई घटनाओं के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले खत के आधार पर इस मामले को बेहद जरूरी बताते हुए संज्ञान में लिया। पत्र के अनुसार, तीन महिला अधिकारियों सहित 7 न्यायिक अधिकारी मालदा जिले के एक गांव में एसआईआर न्यायिक-निर्णय संबंधी कार्यों को पूरा कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इन अधिकारियों को दोपहर 3:30 बजे से आधी रात तक बंधक बनाकर रखा गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्य प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील किए जाने के बाद ही उन्हें मुक्त कराया जा सका। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करे। मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व में यह भी टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से संपन्न हुई है।

मानसून में 10 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधरोपण किया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन पर्यावरण विभाग सहित अन्य विभागों की सहभागिता एवं सक्रियता जरूरी हैं। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना बनाकर निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। सीएम शनिवार को सीएमओ में वन एवं पर्यावरण विभाग के पौधरोपण लक्ष्य, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी स्थापना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।सीएम ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से पौधरोपण प्रारंभ कर मानसून सीजन जुलाई, अगस्त व सितम्बर माह में गति प्रदान की जाएगी। सभी विभाग पौधरोपण लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्थानों का चयन, फेन्सिंग, गड्ढे सहित महत्वपूर्ण कार्य तय समय से पहले पूरे कर लें। विशेष रूप से वन विभाग इस कार्य में सभी विभागों से समन्वय बनाए रखे। रेलवे की परिसंपत्तियों, पीडब्ल्यूडी की सड़कों के किनारे एवं चारागाह में पौधरोपण के लिए कार्य योजना पर काम करें। इस कार्य में वृक्ष मित्रों का भी पूरा सहयोग लिया जाए। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे।

किशनगढ़-जयपुर हाईवे पर हल्के कमर्शियल वाहन, बसों के लिए टोल दरें बढ़ीं

शिवकुमार शर्मा

मदनगंज-किशनगढ़। किशनगढ़ से गुजरने वाले बड़े वाहनों की नेशनल हाईवे-48 पर 1 अप्रैल से यात्रा महंगी हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किशनगढ़ टोल प्लाजा पर वाहनों की टोल दरों में संशोधन किया है। ये नई दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू की गई हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कार्यालय जयपुर के आदेश के बाद बड़गांव टोल प्लाजा पर नई दरों की सूचना चस्पां कर दी गई है। जयपुर-किशनगढ़ सेक्शन टोल प्लाजा पर अब संशोधित दरों के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा। यह संशोधन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत किया गया है।

टोल प्लाजा प्रबंधक बजरंग सैनी ने बताया कि नई दरों के अनुसार, कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए एकल यात्रा शुल्क 55 रुपए और वापसी शुल्क 85 रुपए निर्धारित किया गया है। इन वाहनों के लिए दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हालांकि, हल्के वाणिज्यिक वाहन और मिनी बस के लिए एकल यात्रा शुल्क 90 रुपए और वापसी शुल्क 135 रुपए रहेगा। बस और ट्रक चालकों शुल्क 135 रुपए रहेगा। बस और ट्रक चालकों को अब एकल यात्रा के लिए 190 रुपए व वापसी के लिए 285 रुपए चुकाने होंगे। तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए 205 रुपए (एकल) और 310 रुपए (वापसी) शुल्क तय किया गया है। भारी निर्माण मशीनरी एवं मल्टी एक्सल वाहनों (4 से 6 एक्सल) के लिए 300 रुपए (एकल) और 445 रुपए (वापसी) तथा सात या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए 360 रुपए (एकल) और 545 रुपए (वापसी) टोल निर्धारित किया गया है। स्थानीय वाहन चालकों के लिए भी कुछ राहत का प्रावधान है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए मासिक पास 350 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक वाहनों को जिला पंजीकरण होने पर निर्धारित छूट भी दी जाएगी। किशनगढ़ मार्बल सिटी होने के कारण यहां से भारी वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है। टोल दरों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्ट, मार्बल उद्योग और आम यात्रियों पर पड़ेगा। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इससे परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

पंचायतों और निकायों के चुनाव तय समय में नहीं कराने पर अफसरों को अवमानना नोटिस

ड्ड राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढा की अवमानना याचिका पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने पंचायत चुनाव के मामले में गिरिराज सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका को इस याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव की तय समय सीमा को आगे बढाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि यह सीधे तौर पर अदालती आदेश की अवमानना है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को निर्देश दिया था कि प्रदेश की ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए। इसके साथ ही राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गत फरवरी माह में जारी किए कार्यक्रम में 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया है। इससे साफ है कि किसी भी सूरत में 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। वहीं गिरिराज सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि अदालत ने निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के आदेश दिए थे। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे। ऐसे में अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने को लेकर दंडित किया जाए।

दिन भर इंतजार के बाद भी खरीद केन्द्र पर किसान अपनी फसल का बेचान करने नहीं आए

मदनगंज किशनगढ़। किशनगढ़ उपखंड में सीजन की प्रमुख फसलों सरसों और चना की सरकारी खरीद को लेकर क्रय विक्रय सहकारी समिति ने विधि विधान से मशीनरी यंत्रों की पूजा अर्चना जयपुर रोड कृषि उपज मंडी स्थित खरीद केन्द्र पर की। दिन भर इंतजार के बाद भी खरीद केन्द्र पर किसान अपनी फसल का बेचान करने नहीं आए। हालांकी खरीद केन्द्र पर क्रय विक्रय सहकारी समिति ने खरीद को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है। क्रय विक्रय सहकारी समिति की प्रबधंक नेहा झंवर, महेन्द्र शर्मा, सुरेश शर्मा व मनीष मीना ने विधि विधान से वैदिक मंत्रो के बीच शुभ मुहूर्त में मशनरी की पूजा अर्चना की। खरीदारों ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनो में किसान अच्छी संख्या में आएंगे। पहले दिन शाम तक एक भी किसान अपनी फसल का बेचान करने नहीं आए जबकि प्रतिदिन पंजीयन के हिसाब से बीस किसानों को दूरभाष व मोबाइलन पर फोन करने व मैसेज देकर बुलाया जा रहा है। मालूम हो कि एमएसपी पर पंजीयन का कार्य पन्द्रह मार्च से शुरु हो गया था। रबी की फसल यथा चना व सरसो की खरीद को लेकर जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में क्रय विक्रय समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार चना 5875 रुपए तथा सरसो 6200 सौ रुपए प्रति क्विंटल पर क्रय किया जाएगा। गत वर्ष की अपेक्षा एमएसपी में 0.5 से तीन प्रतिशत वृद्धि की गई है। मंडी में खुली नीलामी में चना व सरसों का भाव एमएसपी से अच्छा मिलने के कारण पंजीयन के बाद भी किसान खरीद केन्द्र पर नहीं पहुंच रहें है। चना 63 सौ और सरसो करीब 65 सौ रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है।

विभाग के अनुसार समर्थन मूल्य पर वही उपज खरीदी जाएगी जो निर्धारित मानकों पर खरी उतरेगी। सरसों की फसल में अधिकतम 8 प्रतिशत नमी की अनुमति, जबकि चना में 14 प्रतिशत तक नमी स्वीकार की जाएगी। इसके अलावा दाने साफ-सुथरे, साबुत और पूरी तरह मिलावट रहित होने चाहिए। एक किसान से अधिकतम 40 क्विंटल चना और सरसों खरीदने का प्रावधान रखा गया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार इस बार किशनगढ़ कृषि क्षेत्र में चना की बुवाई करीब 29 हजार हैक्टेयर तथा सरसों की 11 हजार हैक्टेयर भू भाग में की गई है। इस बार किशनगढ़ में दो खरीद केंद्रों पर राजफैड के माध्यम से सरसों और चने की खरीद की जाएगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके।

बणी ठनी किशनगढ़ शाखा की अध्यक्ष बनी अंजू अग्रवाल

मदनगंज किशनगढ़। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति बनी ठनी शाखा की सत्र 2026-28 की नवीन कार्यकारणी का गठन शुक्रवार को किया गया। नवीन कार्यकारणी में अंजू अग्रवाल को अध्यक्ष, उषा शारदा सचिव और इंदु अग्रवाल को कोषाध्यक्ष का दायित्व सर्वसम्मति से दिया गया। इसके साथ ही कार्यकारणी का विस्तार नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सहमति से किया गया। संस्थापक अध्यक्ष सरोज शर्मा के अनुसार सत्र 2026-28 के लिए सह कोषाध्यक्ष हेमा गर्ग उपाध्यक्ष चीनू अग्रवाल, ललिता शारदा, गुंजन मोदानी शाखा संपादक उमा रांदर, मंजु मालू सह सचिव अंजलि अग्रवाल पर्यावरण प्रमुख संगीता अग्रवाल, सुरुचि अग्रवाल बाल विकास प्रमुख मेघा बंसल, रंजना बांगड महिला सशक्तिकरण प्रमुख मीनाक्षी अग्रवाल, ममता रावका, नेत्र दान देहदान प्रमुख रंजना अग्रवाल, आरती अग्रवाल रक्तदान अंगदान प्रमुख नीता गंगवाल संस्कार संस्कृति प्रमुख सरोज मालू समन्वय प्रमुख हेमा भूतड़ा तकनीकी प्रमुख कृष्णा सोडानी, रिंकी अग्रवाल शाखा जनसंपर्क प्रमुख कुसुम कोठारी कार्यालय संगिनी रितु मंघनानी को नियुक्त किया गया। सभी को पद व गोपनियता की शपथ दिलाई गई।

यादव समाज नवयुवक मंडल का गठन, शंकर टाटला बने अध्यक्ष

मदनगंज-किशनगढ़। श्री यादव अहीर समाज विकास समिति के तत्वाधान में नवयुवक मंडल का गठन किया गया। मंडल का गठन समिति अध्यक्ष कल्याण यादव की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से शकर यादव टाटला को नवयुवक मंडल का अध्यक्ष चुना गया। मंडल अध्यक्ष शंकर यादव द्वारा कार्यकारिणी गठित की गई। जिसमें रूपेश राबड़, ओमप्रकाश जड़वाल जयसिंह घरडवाल को उपाध्यक्ष, इसी तरह दशरथ राबड़ को कोषाध्यक्ष, दिनेश जड़वाल को सह कोषाध्यक्ष, ललित ठोठवाल को महासचिव, बबलू टाटला को सह सचिव, राकेश सुल्तानिया, अंकुश धरडवाल, रामाकिशन बगवाड़िया को संगठन मंत्री, गौतम टाटला व नितेश जड़वाल को प्रचार मंत्री बनाया गया।

बणी ठनी किशनगढ़ शाखा की अध्यक्ष बनी अंजू अग्रवाल

मदनगंज किशनगढ़। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति बनी ठनी शाखा की सत्र 2026-28 की नवीन कार्यकारणी का गठन किया गया। नवीन कार्यकारणी में अंजू अग्रवाल को अध्यक्ष, उषा शारदा सचिव और इंदु अग्रवाल को कोषाध्यक्ष का दायित्व सर्वसम्मति से दिया गया। इसके साथ ही कार्यकारणी का विस्तार नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सहमति से किया गया। संस्थापक अध्यक्ष सरोज शर्मा के अनुसार सत्र 2026-28 के लिए सह कोषाध्यक्ष हेमा गर्ग उपाध्यक्ष चीनू अग्रवाल, ललिता शारदा, गुंजन मोदानी शाखा संपादक उमा रांदर, मंजु मालू सह सचिव अंजलि अग्रवाल पर्यावरण प्रमुख संगीता अग्रवाल, सुरुचि अग्रवाल बाल विकास प्रमुख मेघा बंसल, रंजना बांगड महिला सशक्तिकरण प्रमुख मीनाक्षी अग्रवाल, ममता रावका, नेत्र दान देहदान प्रमुख रंजना अग्रवाल, आरती अग्रवाल रक्तदान अंगदान प्रमुख नीता गंगवाल संस्कार संस्कृति प्रमुख सरोज मालू समन्वय प्रमुख हेमा भूतड़ा तकनीकी प्रमुख कृष्णा सोडानी, रिंकी अग्रवाल शाखा जनसंपर्क प्रमुख कुसुम कोठारी कार्यालय संगिनी रितु मंघनानी को नियुक्त किया गया। सभी को पद व गोपनियता की शपथ दिलाई गई।

स्वामी व प्रकाशक शिवकुमार शर्मा के लिए मुद्रक गजेन्द्र के. बोहरा द्वारा नितिन प्रिन्टर्स, बंगाली गली, कचहरी रोड, अजमेर (राज.) से मुद्रित एवं कार्यालय नन्द निकुंज, जैन स्थानक गली, शिवाजी नगर, मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) से प्रकाशित। सम्पादक : शिवकुमार शर्मा मो. 9829250181, ई-मेल : shiv.ksg@gmail.com

शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और प्रतिकूलता में शरण है।

-अरस्तू

सम्पादकीय

मंगलवार, 7 अप्रैल 2026

अस्थिर होती विश्व व्यवस्था

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था आज मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर खड़ी है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर लड़े जाने वाले संघर्ष नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, पर्यावरण, सृष्टि-संतुलन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता तक पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान और इजरायल के बीच हमलों का नया दौर, अमेरिका की रणनीतिक भूमिका, रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन-ताइवान तनाव जैसे अनेक घटनाक्रम मिलकर यह संकेत दे

रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर हथियारों की दौड़ और शक्ति संतुलन की राजनीति की ओर लौट रही है। यह स्थिति केवल राजनीतिक या सामरिक नहीं, बल्कि मानवीय संकट का संकेत भी है, क्योंकि जब दुनिया हथियारों पर ज्यादा खर्च करती है तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं। आज हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीद रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और सैन्य बजट बढ़ा रहा है। यह एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन विडंबना यह है कि जितने अधिक हथियार बढ़ रहे हैं, दुनिया उतनी ही असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा की यह मानसिकता वास्तव में असुरक्षा का ही परिणाम है। एक देश हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश भी हथियार बढ़ाता है और इस तरह एक अविश्वास का वातावरण बन जाता है। यह अविश्वास ही युद्ध की जमीन तैयार करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दुनिया का सैन्य खर्च कई गुना बढ़ जाएगा और यह पैसा मानव विकास के बजाय विनाश की तैयारी में खर्च होगा। यह स्थिति मानव सभ्यता के लिए शुभ संकेत नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते हमले, समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तनाव और बड़े देशों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी ने इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समुद्री मार्ग खोलने की चेतावनी को खारिज करते हुए ईरान ने इजरायल पर हमलों का नया दौर शुरू किया है, जिससे यह संकट और अधिक गंभीर हो गया है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। हथियारों की होड़ का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे विकास रुक जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी लोग गरीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बजाय हथियारों पर खर्च बढ़ा रही हैं। यह मानवता के साथ एक तरह का अन्याय है। यदि दुनिया का सैन्य बजट का एक छोटा हिस्सा भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए तो दुनिया से गरीबी और भूख को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया की राजनीति अभी भी शक्ति संतुलन और सैन्य प्रभुत्व के इर्द-गिर्द घूम रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व नेतृत्व यह समझे कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शिक्षा और मानव विकास में होती है। जो देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली देश होता है। युद्ध और हथियार केवल विनाश लाते हैं, विकास नहीं। इसलिए दुनिया को यह तय करना होगा कि उसे हथियारों की दुनिया बनानी है या मानवता की दुनिया। यदि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध नहीं रुके और हथियारों की होड़ इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और सामाजिक अस्थिरता जैसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए खतरनाक होगी। इसलिए अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर वैश्विक हितों के बारे में सोचें और युद्ध के बजाय शांति, सहयोग और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाएं। मानव सभ्यता का भविष्य हथियारों से नहीं, बल्कि शांति, संवाद और सहयोग से सुरक्षित हो सकता है। यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। युद्ध का अंधेरा मानवता को केवल विनाश, महंगाई, भय और अस्थिरता देता है, जबकि दुनिया को आज शांति, संवाद और स्थिरता का उजाला चाहिए, और इस दिशा में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज वैश्विक परिदृश्य में भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसे विश्व नेता के रूप में उभरा है जो युद्ध नहीं, संवाद-संघर्ष नहीं, सहयोग और हिंसा नहीं, सहअस्तित्व की बात करता है। भारत बुद्ध, महावीर और गांधी की अहिंसा की परंपरा का देश है, इसलिए भारत यदि सक्रिय कूटनीतिक पहल करे, युद्धरत देशों के बीच संवाद का सेतु बने, संयुक्तराष्ट्र के मंच पर युद्ध विराम की ठोस पहल करे, तो वह विश्व राजनीति को नई दिशा दे सकता है। मोदी यदि शांति, अहिंसा, वैश्विक संवाद और आर्थिक सहयोग के चार सूत्रों पर विश्व को साथ लाने की पहल करें तो भारत वास्तव में विश्व शांति का मार्गदर्शक बन सकता है और युद्ध की दिशा में बढ़ती दुनिया को शांति और स्थिरता की दिशा में मोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है।

शैक्षणिक कलेंडर में सरकार करे शीघ्र संशोधन नहीं तो होगा आंदोलन

मदनगंज-किशनगढ़। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा महासंघ ने पत्र प्रेषित कर राज्य सरकार से शैक्षणिक कलेंडर में संशोधन की मांग की है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि हाल ही है निदेशालय बीकानेर द्वारा शिविरा पंचांग 2026-27 जारी किया गया। जो कि शिक्षको एवं छात्र हितों के प्रतिकूल है। इस संबंध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) द्वारा शिक्षा सचिव व निदेशक को अवगत करवाकर संगठन की मांगो को ध्यान में रखते हुए शिविरा पंचांग जारी करने की सहमति प्रदान की थी। लेकिन जिन तीन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उन तीनों बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होने बताया कि संगठन की शिक्षा अधिकारियों से हुई वार्ता के दौरान अधिकारियों द्वारा ग्रीष्मअवकाश 17 मई से 20 जून किए जाने को कहा गया, जिस पर संगठन द्वारा राजस्थान सेवा नियमो में विगत कई वर्षों से दिए जा रहे ग्रीष्मावकाश की कटौती किए जाने पर आंदोलन के मार्ग अपनाए जाने व ऐसे निर्णय का विरोध करने के लिए कहा गया। जिसके बाद ग्रीष्मावकाश में किसी प्रकार कटौती नहीं करने को लेकर आश्वस्त किया गया। इसके बावजूद प्रासंगिक शिविरा पंचांग में ग्रीष्मावकाशों में कटौती कर 17 मई से 30 जून के बजाय 17 मई से 20 जून तक ग्रीष्मावकाश रखे जाने के आदेश जारी कर दिए।

प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि राजस्थान सेवा नियमो में शिक्षा विभाग, न्यायालय एवं अन्य कुछ विभाग विश्राम कालीन विभाग के रूप में जाने जाते हैं। जिनमें कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश में वेतन दिया जाता है एवं अवकाश दिए जाने कारण 30 के बजाय केवल 15 पीएल ही देय होती है। ऐसे में यदि ग्रीष्मावकाश कम किए जाते हैं तो पीएल 15 के बजाय 30 पीएल अन्य विभाग के कार्मिको की तरह दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि गर्मियों के कारण उक्त अवकाश अवधि में छात्र भी स्कूल नहीं आते। ऐसे में जल्दी स्कूल खोलने के आदेश से छात्रों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रदेश सभा अध्यक्ष संपत सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री बसंत जिंदल, सुषमा बिश्नोई, गीता जैलिया, कैलाश कच्छावा आदि ने बताया कि संगठन की मांग है कि उक्त तीनों बिंदुओं पर वार्ता के दौरान बनी सहमति व आश्वासन के अनुसार ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून यथावत रखने अन्यथा पीएल देने के आदेश पारित करवाए। साथ ही प्रातःकालीन विद्यालय समय 1 अप्रैल के बजाय 1 मार्च से प्रारंभ किया जाए। साथ ही इन सभी आदेशो में संशोधन शीघ्र होना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो संगठन को आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा।

कुमावत समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित

मदनगंज किशनगढ़। कुमावत समाज द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में किरण कुमावत पुत्री मोहनलाल बालोदिया, प्रीति मारोठिया पुत्री मुकेश मारोठिया का माल्यार्पण कर व साफा बंधवाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षत्रिय कुमावत समाज किशनगढ़ परिक्षेत्र अध्यक्ष हरकचंद मारोठिया, आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेनपुरिया किशनगढ़ के निदेशक कैलाश चंद किरोड़ीवाल, अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ जयपुर के संगठन मंत्री एवं प्रदेश संगठन मंत्री नंदकिशोर पारमवाल, परिक्षेत्र उपाध्यक्ष प्रहलाद मारवाल, कुमावत समाज मालियों की बाड़ी अध्यक्ष लालचंद लोहरड़ीवाल, कुमावत पंचायत संस्थान बिहारी पोल किशनगढ़ शहर उपाध्यक्ष महेश मारोठिया सहित कमल कुमावत सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

रसद विभाग ने व्यवासायिक उपयोग करते 5 घरेलू सिलेंडर किए जब्त

मदनगंज-किशनगढ़। रसद विभाग की टीम ने घरेलू सिलेंडर उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई के दौरान नसीराबाद हाईवे स्थित एक होटल व दो चाय -नाश्ते की दुकानों से कुल 5 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। विभाग ने जब्त किए गए सिलेंडरों को अर्जुन गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में रखवाकर उक्त दुकानदारों के खिलाफ ईसी एक्ट 1955 की धारा 6 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं रसद टीम द्वारा शहर की अर्जुन एचपी व केजीएन गैस एजेंसी सहित टांक पेट्रोल पंप का भी औचक निरिक्षण किया। जिसमें अधिकारियों ने दोनों गैस एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर व सिलेंडर डिलीवरी प्रक्रिया की जांच की और संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उपभोक्ता को सिलेंडर की डिलीवरी केवल ओटीपी के माध्यम से करने के लिए कहा।

प्रवर्तन निरीक्षक अंकिता जैन ने बताया कि किशनगढ़ में रसद विभाग द्वारा जांच अभियान जिला रसद अधिकारी द्वितीय नीरज जैन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है जो निरंतर जारी है। किशनगढ़ में घरेलू सिलेंडर के व्यवासायिक उपयोग करने के दौरान रसद टीम ने नसीराबाद हाइवे स्थित सांवरिया भोजनालय, डिसेंट होटल, रामकरण टी रेस्टोरेंट से 5 सिलेंडर जब्त किए। कार्रवाई के दौरान डीएसओ द्वितीय नीरज जैन, अतुल बढाया, मुकेश बुगालिया मौजूद थे।

किशनगढ़ केन्द्रीय बस स्टैण्ड सूना, यात्री परेशान

शिवकुमार शर्मा

मदनगंज किशनगढ़। किशनगढ़ के सुरक्षित यातायात के लिए करीब पैतालीस करोड़ की लागत से जयपुर रोड माता वैष्णव माता मंदिर के सामने बन रहा ओवरब्रीज किशनगढ़वासियों के लिए असुरक्षित बनता जा रहा है। सबसे विचित्र बात यह है कि रोडवेज बस स्टैंड विगत एक माह से सुनसान पड़ा है। आय आधी से अधिक प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद भी रोडवेज का उच्च प्रशासन अनजान व अनभिज्ञ है। विभागीय जानकारी के अनुसार विगत एक माह में तीन करोड़ से अधिक की आर्थिक चोट किशनगढ़ रोडवेज प्रशासन को यह बिना किसी ठोस कदम के किया जा रहा आरओबी निर्माण दे चुका है। इसके बावजूद रोडवेज प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। किशनगढ़ रोडवेज प्रशासन हैरान है कि इस संबंध में अब तक रोडवेज प्रशासन के बड़े अधिकारी पूरी जानकारी से अवगत होने के बाद भी ध्यान क्यों नहीं दिए। मालूम हो कि किशनगढ़ रोडवेज पर विभिन्न आगारों की करीब तीन सौ से अधिक बसों का ठहराव बंद सा हो गया है। एक माह में तीस हजार से अधिक यात्री परेशान हुए। प्रतिदिन एक हजार से अधिक यात्री परेशान हो रहें है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरी ओर जाकर जयपुर की बसे पकड़ने को मजबूर है। मगर कोई बोलने वाला नहीं। फ्लाईओवर (आरओबी) निर्माण कार्य अब यात्रियों

और स्थानीय आमजन के लिए गंभीर परेशानी का कारण बनता जा रहा है।

रोडवेज से यात्रा करने वाले स्थानीय नागरिक व यात्रियों ने जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को लेकर नाराजगी जताई। आमजन ने आरोप लगाया कि एक ओर केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जहां अपने संसदीय क्षेत्र में किशनगढ़ को विशेष महत्व देते है और दूसरी और अजमेर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के एक मात्र तेज तर्रार विधायक व कांग्रेस देहात के जिलाध्यक्ष डा विकास चौधरी किशनगढ़ को अपनी कर्मस्थली बताते है मगर दोनो का ध्यान इस पर नहीं गया। एक माह में पांच से अधिक यात्री गिर कर घायल हो चुके है। दो यात्रियों के पैर में फैक्चर है। इसके अलावा अपने शासन काल में किशनगढ़ के विकास का दंभ भरने वाले जनप्रतिनिधि भी सुप्तावस्था में है। ना भाजपा ना कांग्रेस और ना ही रोलापा या आम आदमी पार्टी इस समस्या को लेकर कोई विरोध जताई। सभी चुनाव में वोट पर अधिकार जताने आएंगे।

इन दिनों अजमेर से जयपुर जाने वाली रोडवेज बसों का किशनगढ़ के आर. के. पाटनी केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर स्टोपेज पूरी तरह बंद कर दिया गया है। परिणामस्वरूप प्रतिदिन करीब 200 से अधिक बसें बाईपास से सीधे जयपुर के लिए निकल रही है और रोजाना 1000 से ज्यादा यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यदि जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, तो यह समस्या किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

ज्ञात रहे कि किशनगढ़ नए बस स्टैंड से प्रतिदिन करीब 400 बसों का संचालन होता था और 1000 से अधिक यात्री सफर करते थे। लेकिन अजमेर-जयपुर रूट की बसों ठहराव बंद होने से रोडवेज को अब तक करोड़ो रुपए के राजस्व नुकसान उठाना पड़ा है। रोडवेज प्रशासन ने आर्थिक नुकसान उठाना कबूल किया मगर वैकल्पिक मार्ग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कराई।

जयपुर से अजमेर आने वाली करीब 200 बसें अब भी केंद्रीय बस स्टैंड पर आ रही है और सवारियां लेकर वैष्णोदेवी धाम के सामने से अजमेर के लिए रवाना हो रही है, वहीं अजमेर से जयपुर जाने वाली बसों का स्टॉप पूरी तरह बंद है। इस एक तरफा यातायात व्यवस्था ने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को असुरक्षित कर दिया है।

दुनिया को चीन की ऊर्जा नीति से सीख लेनी चाहिए

प्राची शर्मा

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच एक सख्त सच्चाई उभर कर सामने आ रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं, लेकिन इस उथल पुथल के बीच चीन एक अलग ही खेल खेलता नजर आ रहा है। जहां एशिया के कई देश ऊर्जा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं चीन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दावा कर रहा है कि उसके पास ऊर्जा का पर्याप्त रणनीतिक भंडार है। दरअसल, यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया। चीन ने पिछले कई वर्षों में एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसने उसे वैश्विक तेल आपूर्ति के झटकों से काफी हद तक सुरक्षित बना दिया है। जब दुनिया तेल के लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर है, चीन ने अपनी निर्भरता को योजनाबद्ध तरीके से कम किया है। सबसे बड़ा बदलाव चीन के इलेक्ट्रिक वाहन अभियान में दिखता है। जहां 2020 में लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक नए वाहनों में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी, वहीं यह आंकड़ा अपेक्षा से कहीं आगे निकल गया और आधे से ज्यादा नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गईं। इसका सीधा असर यह हुआ कि चीन की तेल खपत अब स्थिर होने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण जितना तेल बचा है, वह लगभग उतना ही है जितना चीन सऊदी अरब से आयात करता था। यह बदलाव मामूली नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा भू राजनीति की दिशा बदलने वाला संकेत है। चीन की दूसरी सबसे बडी ताकत उसका विविधीकृत आयात तंत्र है। जहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश एक या दो आपूर्तिकताओं पर निर्भर हैं, वहीं चीन ने अपने तेल स्रोतों को आठ से ज्यादा देशों में फैला रखा है। रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे देशों से सस्ता तेल लेकर उसने पश्चिमी प्रतिबंधों को भी अपने हित में बदल लिया है। रणनीतिक दृष्टि से यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि यदि किसी एक क्षेत्र में संकट आता है, तो चीन पूरी तरह ठप नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक दांव है चीन का विशाल तेल भंडार। अनुमान है कि उसके पास इतना तेल जमा है कि वह होर्मुज मार्ग बंद होने की स्थिति में करीब सात महीने तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। यह भंडारण केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि सामरिक हथियार भी है। देखा जाये तो ऊर्जा सुरक्षा के इस खेल में चीन ने केवल तेल पर ही भरोसा नहीं किया है। उसकी बिजली व्यवस्था लगभग आत्मनिर्भर हो चुकी है। कोयले और तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा के दम पर चीन ने अपने ग्रिड को बाहरी निर्भरता से लगभग मुक्त कर लिया है। इसके साथ ही सौर और पवन ऊर्जा का विस्फोटक विस्तार इस बात का संकेत है कि चीन भविष्य की ऊर्जा लड़ाई के लिए पहले ही तैयार है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि उसे कम एलएनजी आयात करना पड रहा है और तटीय इलाकों की निर्भरता भी घट रही है। गैस के मामले में भी चीन ने चालाकी दिखाई है। पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए उसने रूस, मध्य एशिया और म्यांमार से सीधी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। इससे समुद्री मार्गों पर निर्भरता और कम हो गई है। सामरिक नजरिए से देखें तो यह पूरी रणनीति एक गहरी सोच का परिणाम है। चीन ने समझ लिया था कि भविष्य की जंग केवल हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा पर नियंत्रण से जीती जाएगी। आज जब होर्मुज जलडमरूमध्य पर खतरा मंडरा रहा है, तब भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश चिंता में डूबे हुए हैं। लेकिन चीन इस संकट को अवसर में बदलने की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की तेल मांग अब चरम पर पहुंचकर घटने की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में उसकी आयात निर्भरता और कम होगी, जिससे वैश्विक बाजार में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। बहरहाल, यह पूरा घटनाक्रम एक साफ संदेश देता है। जो देश समय रहते अपनी ऊर्जा रणनीति नहीं बदलेंगे, वे आने वाले संकटों में बुरी तरह फंस सकते हैं। चीन ने यह साबित कर दिया है कि दीर्घकालिक योजना, आक्रामक निवेश और रणनीतिक विविधीकरण के दम पर किसी भी वैश्विक संकट को मात दी जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बाकी दुनिया इस सबक को समझेगी या फिर अगला संकट उन्हें पूरी तरह झकझोर देगा।

युद्ध के चलते मार्बल व्यवसाय में भारी गिरावट

शिवकुमार शर्मा

मदनगंज-किशनगढ़। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे तौर पर भारत के मार्बल उद्योग पर दिखाई देने लगा है। एशिया के सबसे बड़े मार्बल हब किशनगढ़ में आयात और निर्यात दोनों गतिविधियों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच भारत में 17,013 मार्बल ब्लॉक शिपमेंट्स इम्पोर्ट हुई थी। सितंबर 2024 में अकेले 1,808 शिपमेंट्स आई थी। दिसंबर 2025 में यह संख्या अनुमानित 1,450 से 2,100 शिपमेंट्स प्रति माह थी लेकिन मार्च 2026 में यह घटकर लगभग 85 शिपमेंट्स रह गई। यानी कुल मिलाकर करीब 94 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। भारत के मार्बल आयात में तुर्की की हिस्सेदारी करीब 73 प्रतिशत थी। जो अब लगभग शून्य हो गई है। इटली से आने वाली सप्लाई भी प्रभावित हुई है जबकि केवल वियतनाम का सीमित हिस्सा ही चालू है। युद्ध के बाद वैश्विक शिपिंग का प्रमुख मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। पहले वहां से प्रतिदिन 100 से अधिक जहाज गुजरते थे। वहीं अब केवल 21 टैंकर ही ट्रांजिट कर पाए है। बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रूट को बंद कर जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के जरिए डायवर्ट करना शुरू कर दिया है। जिससे ट्रांजिट टाइम और लागत 3 से 4 गुना बढ़ गई है। ईरान-इजराइल तनाव अब केवल इंटरनेशनल मुद्दा नहीं रहा बल्कि इसका असर सीधे भारत के रियल एस्टेट एवं घर बना रहे लोगों के बजट पर पड़ने लगा है। इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स बाधित होने और कंटेनर की भारी कमी के कारण भारत में मार्बल सप्लाई चैन लगभग टूट सी गई है। जिस कारण वर्तमान में मार्बल

के दाम 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ चुके है और यदि यहीं स्थिति जारी रही तो यह बढ़ोतरी 20 से 30 से प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

युद्ध का सबसे ज्यादा असर घर बनाने वाले लोगों और रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ रहा है। जिस कारण बजट 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। मार्बल व ग्रेनाइट की दरों पर युद्ध का प्रभाव पड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख के प्रोजेक्ट पर 5 से 10 लाख रूपए तक का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। मैटेरियल समय पर नहीं मिलने के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है एवं साइट पर काम रुक सकता है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण कराने वाले व्यक्ति को क्वालिटी से भी समझौता करना पड़ सकता है। लोग सस्ता या लोकल मैटेरियल लेने को मजबूर हो सकते है। जिस कारण बाद में मेंटेनेंस दर बढ़ेगी। युद्ध के कारण व्यापार के हालात विकट होते जा रहे है। कंटेनर नहीं मिल रहे है, शिपिंग बुकिंग बंद है, ऑर्डर होल्ड पर है। जिस कारण अनेक कंपनियों का एक्सपोर्ट काम पूरी तरह रुक गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के कारण अभी तक सभी वस्तुओं में मात्र 5 से 10 प्रतिशत तक ही दरें बढ़ी है। जिस कारण स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। अगर हालात यहीं रहे तो 20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी तय है।

फीस कम - कोर्स ज्यादा, बेहतर नौकरी का वादा
आप कम्प्यूटर के क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं.... तो फिर इंतजार किस बात का?
आज ही ज्वाइन करें COMBO COURSE
कोर्स करने के बाद आप बन सकते हैं
COMPUTER OPERATOR
GST ACCOUNTANT
GRAPHIC DESIGNER
E MITRA OPERATOR
START OWN BUSINESS
RS-CIT
GST TALLY
GRAPHICS
S.M.M
WORDPRESS
E-MITRA
TYPING
100% JOB PLACEMENT
मल्टी कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर
MCTC
राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
शार्दूल स्कूल के पास वाली गली, गोपाल कलेक्शन के ऊपर, ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज-किशनगढ़
सम्पर्क करें - 9024480878, 8078652383
REFURBISHED
LAPTOPS
मात्र 9999 रु.*
Lenovo DELL acer ASUS hp Microsoft
SONY COMPAQ TOSHIBA
USED DESKTOP
मात्र 7999 रु.*
Windows 11
SHIV KUMAR SHARMA 9829250181
DNA-293050